(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में लघु और सीमांत किसानों को शामिल करते हुए कृषि के विकास के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेवलपमेंट को आपरेटिव लि0 ने सहकारी संस्थाओं के आधार पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, उसने देश के 10 राज्यों में सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से 50,000 हैक्टेयर परती भूमि को फार्म फारेस्ट्री के तहत लाने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव परती भूमि विकास विभाग को भेजा है।

(ग) और (घ) परती भूमि विकास विभाग ने आर्थिक मामलों के विभाग से इस परियोजना को एक अंतर्राष्ट्रीय दाता अभिकरण के रूप में अर्थात् यू0एन0डी0पी0, एस0 आई0 डी0ए0, विश्व बैंक और जर्मन जैसी एजेन्सी को प्रस्तुतु करने का अनुरोध किया है। प्राथमिक सहकारी सोसायटियों , जो आई0 एफ0एफ0 डी0सी0 की सदस्य बन गई है, के पास छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की बडी संख्या में सदस्यता है ।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना

1674. श्री ईश दत्त यादव:
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार विकास कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कार्य में कोई कठिनाई महसूस हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):

(क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि विकास के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची विवरण के रूप में संलग्र है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, आवधिक प्रगति रिपोर्टो, फील्ड दौरों, श्रेत्रीय अधिकारी की बैठकों, छमाही राष्ट्रीय सम्मेलनों/ क्षेत्रीय सम्मेलनों, आदि के माध्यम से विभिन्न कृषि विकास कार्यो की प्रगति की नियामित रूप से मानिटरिग और समीक्षा कर रही है।

विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों में कार्यन्वित की गई प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र0स0	योजनाओं का नाम	राज्य जहां कार्यान्वित की गई
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	आंध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, मनीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम

क्र0स0	योजनाओं का नाम	राज्य जहां कार्यान्वित की गई
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	आंध प्रदेश, असम बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	आंध प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलानाडु, उत्तर प्रदेश
6.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	सभी राज्य
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	आंध प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाण , जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
8.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा	सभी राज्य
9.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग	उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्य
10.	राष्ट्रीय बीज परियोजना -3	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
11.	राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत आने वाली राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान	सभी राज्य
12.	छोटे किसानों में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा	सभी राज्य
13.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात,हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
14.	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश , पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
15.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास	केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों में परियोजना
16.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	सभी राज्य
17	समेकित काजू विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उडीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
18.	समेकित मसाला विकास	सभी राज्य
19.	भूमि विकास बैंकों के डिबेन्चरों में निवेश	सभी राज्य